ज़ोखिम पर ध्यान दें।

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

16 दिसम्बर, 2021

मंगलवार को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचा पेश किया। ढांचे को उपयुक्त समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इकाई को स्वास्थ्य में वापस लाने में मदद मिलती है, और बड़ी वित्तीय प्रणाली पर नतीजे सीमित होते हैं।

इसके तहत, एनबीएफसी के कुछ मापदंडों जैसे खराब ऋण और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की निगरानी की जाएगी, और जब ये मानदंड पूर्व-निर्धारित स्तरों से नीचे आते हैं, तो केंद्रीय बैंक अलग-अलग डिग्री में एनबीएफसी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा। यह ढांचा अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा, जिससे एनबीएफसी को अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने का समय मिलेगा, जो महामारी के आर्थिक नतीजों के कारण प्रभावित हो सकते हैं। इस कदम के साथ, आरबीआई एनबीएफसी के पर्यवेक्षी ढांचे में बैंकों के साथ कुछ सरेखण लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ढांचे के तहत, केन्द्रीय बैंक ने तीन संकेतकों को लिया है, अर्थात् जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर), टियर 1 पूंजी अनुपात और शुद्ध एनपीए अनुपात (एनएनपीए) के लिए पूंजी तीन जोखिम सीमाओं को चित्रित करने के लिए। यदि इन मापदंडों पर किसी एनबीएफसी की स्थिति बिगड़ती है, तो इकाई जोखिम प्रोफाइल पर आगे बढ़ेगी। और जैसे-जैसे इसका जोखिम प्रोफाइल बिगड़ता जाएगा, आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की गंभीरता बढ़ती जाएगी। ये लाभांश के वितरण पर प्रतिबंध, गारंटियों पर प्रतिबंध और समूह की कंपनियों की आकस्मिक देनदारियों को लेने के साथ शुरू होते हैं, और प्रमोटरों/ शेयरधारकों को इकाई में इक्विटी डालने और लवरेज को कम करने की आवश्यकता होती है।

उच्च जोखिम सीमा पर, शाखा विस्तार, पूंजीगत व्यय और परिचालन लागत पर भी अंकुश लगाया जाएगा। पीसीए ढांचे से बाहर निकलना और प्रतिबंधों में ढील देना एनबीएफसी द्वारा लगातार चार तिमाहियों तक जोखिम सीमा का उल्लंघन नहीं करने पर सशर्त होगा। इस खंड के आकार में बढ़ने के साथ– एनबीएफसी क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 2020 में आरबीआई के अनुसार 11.6 प्रतिशत था- और वित्तीय प्रणाली के अन्य हिस्सों के साथ तथा मजबूत संबंधों के साथ, उनकी संपत्ति की गुणवत्ता को बारीकी से देखा जाना चाहिए। जमा स्वीकार करने वाली बड़ी एनबीएफसी के लिए तो और भी बहुत कुछ। कार्रवाई करने में देरी केवल मामलों को जटिल बनाती है, जिससे वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) जैसी एनबीएफसी का पतन, वित्तीय बाजारों में गिरावट और बड़ी अर्थव्यवस्था, सॉल्वेंसी के मुद्दों में तरलता के मुद्दों का भूत, केवल आवश्यकता को रेखांकित करता है इस तरह के ढांचे के लिए वित्तीय तनाव को पहले संबोधित करने से संबंधित लागत कम हो जाती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में आरबीआई ने एनबीएफसी के जोखिम को जाँचने को लेकर निम्नलिखित में से कौन से संकेतक निर्धारित किये हैं?

(a) जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर)

(b) टियर 1 पूंजी अनुपात

(c) शुद्ध एनपीए अनुपात

(d) उपर्युक्त सभी।

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Which of the following indicators have been prescribed by RBI recently to measure the risk of NBFCs?

(a) Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)

(b) Tier 1 Capital Ratio

(c) Net NPA Ratio

(d) All of the above.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के लिए बनाए गए नए दिशानिर्देश क्या है तथा आरबीआई का यह नियंत्रण किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर सिद्ध होगा? (250 शब्द)

Q. What are the new guidelines recently made by RBI for NBFCs and how will this control of RBI prove to be better for the economy? (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।